

संपादकीय

मस्क और ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड को बड़ा झटका

अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नीति विभाग की संवेदनशील जानकारी हासिल करने पर रोक लगा दी है। संघीय न्यायाधीश ने पूँजीपति एलन मस्क नीति सरकारी दक्षता विभाग को वित्त विभाग के रिकार्ड हासिल करने पर रोक लगाई जिसमें लाखों अमेरिकियों की सामाजिक सुरक्षा व बैंक खाता संबंधी संवेदनशील जानकारी व डेटा शामिल हैं। यह आदेश उत्तीर्ण डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरलों द्वारा ट्रंप पर दायर किये गये मुकदमे के बाद जारी किया। एक अन्य संघीय अदालत ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी। अदालत का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने संघीय कानून का उल्लंघन करते हुए मस्क की टीम को वित्त विभाग की केंद्रीय भुगतान प्रणाली तक पहुंचने की अनुमति दी जिसके तहत रिफंड, सामाजिक सुरक्षा लाभ, पूर्व सैनिकों को लाभ समेत तमाम जिम्मेदारियां आती हैं। यह प्रति वर्ष लाखों-करोड़ों डॉलर का लेन-देन करती है। ट्रंप के सत्ता संभालते ही उनके प्रशासन ने सरकारी फिजूलखर्ची का पता लगाने और उसे खत्म करने के लिए मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग यानी डीओजीआई का गठन किया था। हजारों विदेशी कर्मचारियों को तीस दिन के भीतर परिवार समेत लौटने के आदेश को रोकते हुए अदालत ने इसे जल्दबाजी में किया गया फैसला बताया। अदालत का यह रुख दिग्गज कारोबारी मस्क और ट्रंप, दोनों को बढ़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व ही मस्क ने ट्रंप के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। राष्ट्रपति बनते ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप के इमीग्रेशन, टैरिफ, जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से पांच खींचने जैसे चौंकाने वाले फैसलों पर दुनिया हत्प्रभ थी। उनके तेवरों से विपक्ष ही नहीं, विश्व समुदाय भी आर्शकित है। उहोंने कहा है कि हम युद्ध में नहीं पड़ेंगे, शांति लायेंगे जबकि यूक्रेन का जिक्र भी नहीं किया, न ही गाजा के विषय में कुछ स्पष्ट किया। अमेरिका महंगाई के साथ कानून-व्यवस्था से जूँझ रहा है। अमेरिकी व्यवस्था में अदालतों के अधिकारों को चुनौती देना आसान नहीं है। मगर ट्रंप दूसरे कार्यकाल में पूर्वग्रहों से भरे एजेंडों को लेकर काफी आक्रामक हैं। न सिर्फ बजिद नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने मसूबों को लेकर अड़े भी हुए हैं।

आलेख

शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञानार्जन

रजनीश कपूर

आवश्यक है कि विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ परीक्षाओं में सफलता का मूल्यांकन केवल अंकों के आधार पर न किया जाए, बल्कि छात्रों की संपूर्ण योग्यता और कौशल को ध्यान में रखा जाए। जब शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञानार्जन बनेगा, तभी समाज का वास्तविक विकास संभव होगा। देश में वार्षिक परीक्षाएँ छात्रों के भविष्य को निर्धारित करने का प्रमुख माध्यम हैं। लेकिन हाल के वर्षों में, शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जन से हटकर केवल उच्च अंक प्राप्त करने तक ही सीमित होता जा रहा है। खासकर देहाती क्षेत्रों के विद्यार्थी अब नियमित कक्षाओं में पढ़ने की बजाय कोचिंग सेंटरों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कम समय में अधिक अंक प्राप्त करने के आसान तरीके बताए जाते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के समग्र विकास के लिए भी एक चुनौती बनती जा रही है। देश के गाँवों के छात्रों में एक नई होड़ देखी जा रही है। देहाती छात्र काफी मात्रा में विद्यालय से विमुख हो रहे हैं। इसके पीछे शिक्षा प्रणाली की कई खामियाँ ज़िम्मेदार मानी जा सकती हैं। इनमें अहम हैं ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कमज़ोर आधारभूत संरचना और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री के कारण विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में रुचि नहीं लेते। इसके अलावा कोचिंग संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि छात्रों को लगता है कि विद्यालय में पढ़ने की तुलना में कोचिंग सेंटरों में परीक्षा के लिए विशेष तरीके सिखाए जाते हैं। जिससे वे कम समय में ले लांगों और खासकर महिलाओं का केजरीवाल ने न सुविधाएँ मुहैया कराई उनसे ज्यादा उन्होंने भविष्य मिलने का वादा की गई सुविधाओं पर भरोसा व भाजपा को उम्मीद से ज्यादा बोट दिए। या यूँ कहिए कि मोदी है तो मुमकिन हुआ पर साथ ही यह भी न भूलना चाहिए कि आप पार्टी के पिछले तीन चुनावों मोदी प्रधानमंत्री हैं पर तब क्यूँ नहीं मोदी मुमकिन हो सका। तभी इन चुनावों के जरीवाल की हार के बाद यह कहावत भी सटीक कि वक्त तो ऊँट पर बैठा नेता केजरीवाल चुनाव ह गए। दिल्ली में महिलाओं को मिल रहीं सुविधाएँ गर्भ चर्चलीं गई भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं पर भरोसा हुआ और ऐसा कि एक दशक से सत्ता में बैठे केजरीवाल और उनकी पार्टी का राजनीति का न उतर गया। महिलाओं ने पुरुषों से कहीं अधिक बोंध भाजपा डाल जाता दिया कि केजरीवाल को देखलिया अब भाजपा को देखेंगे। महिलाओं ने जहाँ 61.9% फीसद बोट डाले वहाँ पुरुषों ने 60.21 ही बोट डाल यही नहीं बोटिंग में भी महिलाएँ आगे रहीं। तभी कैसा जा रहा है कि भाजपा की इस जीत में महिला फैक्टर

अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह धारणा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्हाँ नहीं गांव के भोले भाले युवकों को लुभाने की मंशा से कई कोचिंग सेंटर यह दावा भी करते हैं कि वे छात्रों को परीक्षा में अधिक अंक दिलाने में मदद करें। जिससे अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की बजाय कोचिंग में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे में यदि शिक्षक भी उदासीन रवैया अपनाना शूर कर दें तो वह आग में घी का काम करता है। ऐसा भी देखने में आया है कि ग्रामीण इलाकों के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी या उनकी लापरवाही के कारण कक्षाओं का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में छात्र कोचिंग का विकल्प चुनने को मजबूर हो जाते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व थ्री इडिअट्स' फ़िल्म में भी यह दिखाया गया था कि अधिक अंकों की होड़ का छात्रों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि होना यह चाहिए कि अगर हर नौजवान को अपने दिल की आवाज सुनकर अपनी जिंदगी की राह तय करनी चाहिए। यदि वो अइस करता है तो वह खुश भी होता है और सही मायने में सफल भी। केवल ज्यादा पैसे कमाने के लिए बिना समझे रहा मारने वाले कोल्हू के बैल ही होते हैं। जिनकी जिंदगी में रस नहीं आ पाता। यही कारण है कि आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर सैकड़ों नौजवान आज देश में ऐसे काम कर रहे हैं जिसका उनकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। मसलन झुग्यियों में बच्चों को पढ़ाना, आध्यात्मिक आन्दोलनों में भगवतीता का प्रचारक बनना या गांव के नौजवानों के लिए छाटे-छोटे कृती उद्योग स्थापित करने में मदद करना। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग की डिग्री की भूख इस कदर बढ़ गयी है कि एक-एक शहर में दर्जनों प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं। जिनमें दाखिले का आधार योग्यता नहीं मोटी रकम होता है। इन कॉलेजों में योग्य शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी रहती है। फिर भी यह छात्रों से भारी रकम फीस में लेते हैं। बेचारे छात्र अधिकतर ऐसे परिवारों से होते हैं जिनके लिए यह फीस देना जिंदगी भर की कमाई को दाव पर लगा देना होता है। इन्हाँ रूपया खर्च करके भी जो डिग्री मिलती है उसकी बाजार में कीमत कुछ भी नहीं होती। तब उस युवा को पता चलता है कि इन्हाँ रूपया लगाकर भी उसने दी गयी फीस के ब्याज के बराबर भी पैसे की नौकरी नहीं पाई। तब उनमें हताशा आती है। आज हालत यह है कि यों की दुकानों पर सेल्समैन का काम कर रहे हैं। समय और पैसे का इससे बड़ा दुरुपयोग और क्या हो सकता है? इसलिए समझ की बजाय रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करने में ही समझदारी है। लेकिन देखा यह गया है कि कुछ कोचिंग संस्थान परीक्षा पास करने के लिए रटने पर जोर देते हैं।

देश के बंद

केआर भारती

आशा की जानी चाहिए कि प्रदेश के तीथ देवस्थलों के विकास व उनकी कोविटिटी बढ़ाने लिए केंद्र से उचित सहायता प्राप्त होगी। पहाड़ी क्षेत्रों मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी विचार है केंद्र बजट पर देश के प्रत्येक राज्य व समाज के प्रत्येक व की निगाहें टिकी रहती हैं कि उन्हें इससे क्या मिल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 को 2025-26 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए देश के विकास और कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। लेकिन बिहार और असम सिवाय किसी राज्य का विशेष जिक्र नहीं हुआ। जबिहार में मखाना बोर्ड और असम में युरिया संघ स्थापित करने का विशेष उल्लेख किया गया, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य कह उठे कि हम राज्य को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। राष्ट्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों से हर राज्य को लाभ मिलता आया है और मिलता ही रहेगा। आखिर हमारा भारत, संघीय ढांचा ही तो है। राज्यों व मिल कर ही देश बना है। देश में एक ही तो नागरिक है। जो देश का है वह राज्यों का भी है। यहाँ बजट की गई कुछ घोषणाओं का जिक्र करना जरूरी जिससे अन्य राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश व भी बहुत फ़यदा मिलने वाला है। कृषि व बागवानी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लागू करने व घोषणा हुई है जिसमें कम उत्पादकता, कम फसलों व बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 10

अनिल चतुर्वेदी

कहते हैं वक्त खराब हो तो ऊँट पर बैठे अदामी दिकुचा काट लेता है। दिल्ली विधानसभा के इन चुनाव उत्तमता है अरविंद केजरीवाल केजरीवाल और उनकी आप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दिखा। दिल्ली नेगर्मांगों और खासकर महिलाओं को केजरीवाल ने रखी विधायें मुहैया कराई उनसे ज्यादा उन्होंने भविष्य बताने का वादा की गई सुविधाओं पर भरोसा बनाया को उम्मीद से ज्यादा बोट दिए। या यूँ कहिये मोदी है तो मुमकिन हुआ पर साथ ही यह भी नहीं बताना चाहिए कि आप पार्टी के पिछले तीन चुनावों में प्रधानमंत्री हैं पर तब क्यूँ नहीं मोदी मुमकिन ना सार्थक हो सका। तभी इन चुनावों में भी भरीवाल की हार के बाद यह कहावत भी सटीक बक्त तो ऊँट पर बैठा नेता केजरीवाल चुनाव हार दिल्ली में महिलाओं को मिल रहीं सुविधाएँ गर्भीय में गई भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं पर भरोसा और ऐसा कि एक दशक से सत्ता में है भरीवाल और उनकी पार्टी का राजनीति का नहीं रह गया। महिलाओं ने पुरुषों से कहीं अधिक वंशज जपा डाल जाता दिया कि केजरीवाल को देखलिया भाजपा को देखेंगे। महिलाओं ने जहां 61.9 प्रसद बोट डाले वहीं पुरुषों ने 60.21 ही बोट डाले नहीं बोटिंग में भी महिलाएँ आगे रहीं। तभी क्या रहा है कि भाजपा की इस जीत में महिला फैक्टर

देश के केंद्रीय बजट और हमारा प्रदेश...

केआर भारती

आशा की जानी चाहिए कि प्रदेश के तीथे देवरथलों के विकास व उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने लिए केंद्र से उचित सहायता प्राप्त होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में डिक्टील टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी विचार है केंद्रीय बजट पर देश के प्रत्येक राज्य व समाज के प्रत्येक व की निगाहें टिकी रहती हैं कि उन्हें इससे क्या मिल सकेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फव 2025 को 2025-26 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए देश के विकास और कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। लेकिन बिहार और असम सिवाय किसी राज्य का विशेष जिक्र नहीं हुआ। जब बिहार में मखाना बोर्ड और असम में यूरिया संघ स्थापित करने का विशेष उल्लेख किया गया, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य कह उठे कि हम राज्य को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। राष्ट्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों से हर राज्य को लाभ मिलता आया है और मिलता ही रहेगा। आखिर हमारा भारत, संघीय ढांचा ही तो है। राज्यों व मिल कर ही देश बना है। देश में एक ही तो नागरिक है। जो देश का है वह राज्यों का भी है। यहां बजट की गई कुछ घोषणाओं का जिक्र करना जरूरी जिससे अन्य राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश व भी बहुत फयदा मिलने वाला है। कृषि व बागवानी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लागू करने व घोषणा हुई है जिसमें कम उत्पादकता, कम फसलों व बुराई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 10

आप का जात का आधार बना था। आर इस बार भा महिलाओं की लिए सुविधाओं का पिटारा खुलना था जिसमें पूरी बस के अलावा महिला सम्प्रभाव योजना में 2100 रूपये हर महीने देने का बादा था। यही नहीं कांग्रेस की तरफ से भी 2500 रूपये हर महीने देने का बादा था और साथ ही गरीब महिलाओं को 500 में सिलेंडर के अलावा त्योहार पर पर पूरी गैस सिलेंडर के अलावा 2100 रूपये भी देने का बादा था। लेकिन भाजपा की ओर से बुजुर्गों को पेंशन, 2000 रूपये हर महीने से बढ़ाकर 2500 के अलावा पेंशन राशि बढ़ाने के साथ ही दुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन और फिर मोदी की गारंटी पर पर ज्या भरोसा कर भाजपा के लिए बोट दिए। और भाजपा ने 70 में 48 सीटें जीतीं। भला हो दिल्ली के लोगों और खासकर महिलाओं का कि भाजपा उनसे किए गए वादों को पूरा करें और अगले चुनावों के लिए अपनी ज़मीन पक्की पर अगर इन वादों और के जरीवाल की योजनाओं को जारी रखने का बाद पूरा करने की बजाए इन्हें पिछले चुनावी वादों की तरह चुनावी जुमला करार दे दिया गया तो क्या तो होगा वादों का और कैसे कहेंगे लोग कि मोदी है तो मुमकिन है। विधानसभा चुनावों में 70 सीटों में से 48 सीटें जीतने वाली भाजपा के समाने अब दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनें की चुनौती है। यूं सीएम बनने की चाहत में दिल्ली भाजपा के पुराने और धुरंधर नेता चुनाव जीतने के बाद से गणेश पर्किंसा लगे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री

जिलों में उत्पादकता व भंडारण बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। सिंचाई सुधार के साथ-साथ किसानों को दीर्घ व लघु अवधि के त्राय उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश से भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक जिले को चुने जाने की संभावना है। पहले भी सबसे कम विकसित जिलों की आर्थिक प्रगति के लिए चलाई गई एकांकी जिला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को चुना गया था। फल व सब्जी उत्पादन व खाद्य और फल प्रसंस्करण के लिए भी देश में व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश, देश के फल राज्यों में से एक है। राज्य में सेब की पैदावार सबसे अधिक होने के कारण इसे सेब राज्य की संज्ञा दी गई है। हिमाचल प्रदेश को गैर मौसमी सब्जियां उगाने की भी महारत हासिल है। ऐसे में हमारे बागवानों और सब्जी उत्पादकों को भी लाभ मिलना सुनिश्चित है। केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले त्रैशों की त्राय सीमा तीन लाख से पांच लाख तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। हिमाचल में 10 लाख के करीब सीमांत, लघु, मझली और बड़ी किसानी जोते हैं। इस बढ़ोतारी का लाभ हिमाचल के खेती किसानों, डेयरी किसानों और यहां तक कि मछुआरे भी उठा सकते हैं। प्रदेश में 13000 के लगभग मछुआरे हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप (सूक्ष्म और मध्यम उद्यम), एमएसएमई व स्टार्टअप के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को 2.5 व 2.0 गणा बढ़ाया जा रहा है। उन्हें



ऋण तक पहुंच बनाने के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ा की घोषणा भी हुई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए रुपए 5 करोड़ से रुपए 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ा कर 20 करोड़, उत्तम चलने वाले नियंत्रित एमएसएमई के लिए रुपए 20 करोड़, सावधि ऋण की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को भी इससे लाभ पहुंचेगा और उद्यमियों के साथ-साथ प्रदेश में युवाओं के लिए भी रोजगार बढ़ेगा। प्रदेश में इस समय 136000 उद्यम पंजीकृत जिसमें 97.5 प्रतिशत सूक्ष्म, 2.37 प्रतिशत लघु और 0.28 प्रतिशत मध्यम किस्म के हैं। शिक्षा और कौशल विकास : बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने की उद्देश्य से देश में पहले से ही अटल टिकिरिंग लैब कार्यक्रम चल रहा है। अगले पांच साल में 50000 और अटल टिकिरिंग लैब खोले जाने का प्रस्ताव है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के बच्चों का विद्यालय इस सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय नेटवर्क

अलावा प्रतिद्वंद्वी भाजपा के रमेश बिधूड़ा आर काग्रस की अलका लांबा का भी शुरूगुज़ार करना चाहिए। इनमें से भी रमेश बिधूड़ी का खासतौर से। भाजपा के सांसद रहे बिधूड़ी अपने व्यवहार और बेबाकी के लिए पहचाने जाते रहे हैं भले संसद हो या फिर विधानसभा चुनाव सीट। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों संसद में अपने ही एक साथी को गरिआया उसी तरह उन्होंने इन चुनावों में दिल्ली की मुख्यमंत्री और इस चुनाव में कालकाजी से आप पार्टी की दावेदार और उनकी प्रतिद्वंद्वी आतिशी को भी उन्होंने खूब गरिआया। संसद में उनकी बेबाकी को तो पार्टी ने अनदेखा कर दिया था पर शायद दक्षिण दिल्ली की इस सीट के बोटरों को उनका मिजाज भाया नहीं। और जबाब उन्हें अपने बोट से दिया। सच पूछो तो इस हार के बाद वे दिल्ली का सीएम बनने की इच्छा से चूक गए। वरना तो बिधूड़ी का चेहरा सीएम के बाकी चेहरों से कोई कम नहीं था। कमोवेश ऐसा ही कांग्रेसी की अलका लांबा के साथ कांग्रेसी नेताओं के व्यवहार से भी आतिशी को राहत मिली। यह अलग बात है कि अलका को उनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर लड़ाया गया, वे हार्ने और इसका लाभ आतिशी को सौ फ़ीसद मिला। पर कोई कहे कि अलका हार्ने तो अलका जीत सकतीं थी बशर्ते कांग्रेसी साथ देते। पर कौन जानता था कि अलको को हराने और एक कांग्रेसी नेता की यह इच्छा पूरे करने के लिए कि अलका को 5000 से ज्यादा बोट नहीं मिल सकें ते

परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यम पाठशालाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जिसमें हिमाचल के भी कई स्कूलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत स्कूल और उच्चतर में शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान की जाएंगी जिससे प्रदेश के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। आईआईटी में प्रवेश के लिए आगामी वर्ष 6500 अतिरिक्त सीटें और मेडिकल कॉलेजों में 10000 नई सीटें सृजित होंगी। मेडिकल कॉलेजों में आगामी पांच सालों में 75000 नए प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव है, जिससे हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इसी तरह कौशल निर्माण के लिए देश में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं जिससे राज्य के युवक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य : केंद्रीय बजट में कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से 36 जीवन रक्षक दवाइयों को बुनियादी सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। कुछ अन्य जीवनरक्षक दवाइयों को 5 पैसदी रियायती सीमा शुल्क की सूची में डाला गया है। इससे रोगियों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। अगले तीन सालों में देश के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में डे-केयर सेंटर स्थापित होंगे। जाहिर है कि हिमाचल के भी सभी जिले चरणबद्ध तरीके से इससे लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन कंपनियों में डिलीवरी के साथ जुड़े या अन्य अस्थायी कर्मचारी जिन्हें गिर वर्कर्स कहा जाता है, को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है जो अत्यंत सुखद है।

ओपन थिएटर से गढ़कलेवा में शिप्ट कराई गई चैपाटी

कोरबा(विश्व परिवार)। कोरबा अंचल के ओपन थिएटर क्षेत्र में खोमचा कारोबार को संचालित करने की जिद कर रहे व्यवसायियों को आधिकारिक गढ़कलेवा में जाना पड़ा। निगम के बाबत पर उन्हें गढ़कलेवा में भेज दिया गया है। संतुष्टि के लिए प्रवेश द्वार पर चैपाटी लिख दिया गया है ताकि संदेह दूर हो सके कोरबा जिला नार निगम का कहाना है कि जिस उद्देश्य से गढ़कलेवा बनाया गया और उस पर कई प्रकार के सुधार कराए गए ऐसे में उपयोगिता तय होना चाहिए। बेमन से नई जगह पर पहुंचे कारोबारियों ने पिछे दोहराया कि व्यवसाय की स्थिति देखेंगे और अच्छे नतीजे नहीं आने पर फिर पुरानी जगह पर आएंगे। फस्ट पूफ से लेकर कई प्रकार के खानपान की चीजों की आधारित खोमचा कारोबार से जुड़े हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कोरबा के ओपन थिएटर क्षेत्र में समय से अपनी दुकान लगाते रहे हैं।



लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इनसे अलग हटकर इन्हीं संख्या में ऐसे कारोबारी के महानदी कालेक्स, निहारिका, कोसावाड़ी, ड्रांसपोर्ट नार, सीएसईवी चैक, और बिज अग्रसेन रोड से लेकर सीतामढ़ी तक अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन्हें इनकी आमतः अपने परिवार को आसपास खोमचा कारोबार करने लोगों को हटाना पड़ता है। इस पर भी उनकी नाराजगी स्वाभाविक रूप से सपने परिवार की व्यवसाय की गई है। इस रखते हुए नार पालिक निगम ने लोगों को मोंके पर जगह दी गई है और कहा गया है कि अब उन्हें यहाँ पिछले वर्षों में लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर नजदीक में ही गढ़कलेवा को विकसित किया।

जिसके जरिए अपने परिवार को सभा स्थल के आसपास खोमचा कारोबार करने लोगों को हटाना पड़ता है। इस पर भी उनकी नाराजगी स्वाभाविक रूप से सपने परिवार की व्यवसाय की गई है। इस आधारित प्रकार के खानपान की चीजों की आधारित खोमचा कारोबार से जुड़े हुए लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कोरबा के ओपन थिएटर क्षेत्र में समय से अपनी दुकान लगाते रहे हैं।

हालांकि कुछ महीने तक ही इस स्थान पर छोटीसाढ़ी व्यंजनों के साथ दूसरे कारोबार चल सके। चौरी-चकारी के काम में लगे तत्वों की गतिविधियों से यहाँ का काम प्रायः सामान चौरी हो गया और इसी बहाने के साथ कारोबार करने वाले लोगों के साथ काम करें। इस लोग एक बार फिर से ओपन थिएटर मिली लेकिन निगम ने आधिकारिक गढ़कलेवा को ही चैपाटी के नए नाम से संगठित किया। इस जगह पर याहाक नहीं आने और व्यवसाय की अर्थिक स्थिति के आधार पर चौरीजों की नीति बनाई और इस पर कियान्वयन करना सुनिश्चित किया। इस जगह पर याहाक नहीं आने और व्यवसाय की अवधि बढ़ावा देने की बात करते हुए तीन टेलों पर जेसीबी चला दी, जिससे वहाँ होगामा मच गया। कोरबा नार निगम ने ओपन थिएटर ग्राउंड के पास गढ़कलेवा में एक व्यवसाय चैपाटी तैयार की, जहाँ टेले-खोमचे वालों को बिजली, पानी सहित अन्य व्यवसाय के लिए ग्राउंड प्रदान की गई थी। इसके बावजूद कई व्यापारियों ने वहाँ जाने से इंकार कर दिया और खुले मैदान में ही टेले लगाने लगे। इस पर नार निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निरेश जारी किए कि यदि चैपाटी का संचालन करना है तो निर्धारित स्थान पर ही किया जाए, अन्यथा अवधि रूप से संचालित टेले हटा दिए जाएं। उक्त आदेश का पालन करते हुए नार के अधिकारियों टेले व्यवस्था नवीन जगह पर की गई है उसके अपने मायने हैं और यहाँ पर याहाक नहीं आने और व्यवसाय की अवधि बढ़ावा देना है। इस बारे में किसी प्रकार के दूसरे विकल्प अपनाने और समझौते करने की जरूरत नहीं है।

बालको हॉस्पिटल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ डायलिसिस यूनिट की शुरुआत

कोरबा-बालकोननगर(विश्व परिवार)। बालको हॉस्पिटल में किडनी रोगियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई है। इस अत्याधुनिक यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जिन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती है। बालको हॉस्पिटल वर्षों से क्षेत्र में गुणवत्ता-पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगियों को बेहतर इलाज



अवैध रूप से महुआ शराब बना रहे दो आरोपी गिरफ्तार

कोरबा(विश्व परिवार)। जिले की दोपाक थाना पुलिस ने ग्राम केराकारा रूप से अवैध रूप से महुआ शराब बनाने तथा भंडारण करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 180 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने में प्रयुक्त गैस सिलेंडर, चूल्हा, बत्तन जबकि किया है। बता दें कि पुलिस अधिकारी, जिला कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशनुसार अतिरिक्त पुलिस अधिकार उपस्थिति थे। बता दें कि यूनिट का शुरुआत प्राप्ति विवेक को आरोपियों को बेहतर इलाज की जिसकी

नायडू, सीईओ वेदांता रिसोर्सेस द्वारा किया गया। इस अवसर पर नवीनीतम रोगियों और तकनीकों का विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

नायडू, सीईओ वेदांता रिसोर्सेस द्वारा किया गया। इस अवसर पर नवीनीतम रोगियों और तकनीकों का विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना से उन मरीजों को विशेष विकारी के मुख्य कार्यकारी का विशेष विकारी रोगी कुराक तक साथ मरीजों को विशेषताएं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाती है। डायलिसिस यूनिट की शुरुआत के साथ, अब किडनी रोगी को सुलभ और उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्ति देनी होती है।

सिन्हा ने बताया कि इस यूनिट की

